GK/GS का
महा संग्राम

POLITY

भारत का संवैधानिक विकास
(DEVELOPMENT OF INDIAN CONSTITUTION)

हमारे **TOPIC EXPERT** के साथ

देखे शाम 07:00 बजे

LIVE

BY GS GURU

CONSTITUTION
OF
INDIA
भारत का संविधान

संविधान का निर्माण कैसे हुआ?

How was the Constitution made?

GS/GK का महासंग्राम

Like Share

(1773 - 1857) → कंपनी शासन

भारत का संवैधानिक विकास

(Constitutional Development of India)

(1858 - 1947) → ताज शासन

Constitutional Development

- भारत में ऐतिहासिक ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों की अवधि को दो चरणों में विभाजित किया जा सकता है:
- चरण 1- ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन (1773-1857)
- चरण 2 -ब्रिटिश क्राउन का शासन (1857-1947)
- The period of historical British Constitutional experiments in India can be divided into two phases:
- Phase 1- East India Company Rule(1773-1857)
- Phase 2 –British Crown Rule (1857-1947)

Constitutional Development

- भारतीय संविधान की उत्पत्ति और विकास की जड़ें ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय इतिहास में हैं। 1773 के बाद से, भारत के शासन के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित किए गए।
- The origin and growth of the Indian Constitution have its roots in Indian history during the British period. From 1773 onwards, various Acts were passed by the British Government for the governance of India.

ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन

East India Company Rule

(1773 – 1857)

E
I
Co.
BRITISH EAST INDIA COMPANY
1600 - 1874
British East India Company
By Gerald Kuchy

Regulating Act of 1773

- भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित यह पहला अधिनियम है।
- इस अधिनियम के अनुसार, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर-जनरल बनाया गया था।
- वारेन हेस्टिंग्स भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे।
- This is the first Act passed by the British Parliament to control and regulate the affairs of the East India Company in India.
- As per this Act, the Governor of Bengal was made the Governor-General.
- Warren Hastings was the first Governor-General of India.

Regulating Act of 1773

- रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रावधानों के अनुसार 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी।
- सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 सहायक न्यायाधीश थे।
- A Supreme Court was established at Calcutta in 1774, as per the provisions of Regulating Act 1773.
- The Supreme Court had a Chief Justice and 3 Assistant Judges.

Pitts India Act of 1784

- 1784 के इस अधिनियम के अनुसार, ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को "भारत में ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्र" कहा गया।
- पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के प्रावधानों के अनुसार वाणिज्यिक संचालन के लिए एक निदेशक मंडल का गठन किया गया था और राजनीतिक मामलों के लिए 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड नियुक्त किया गया था।
- As per this Act of 1784, the territories of East India Company was called as the "British Possessions in India"
- A Court of Directors was formed for Commercial Operations and 6 member Board of Control were appointed for Political affairs as per provisions of Pitts India Act 1784.

Charter Act of 1813

- इसने भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया।
- चाय व्यापार को छोड़कर भारत के साथ व्यापार सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए खोल दिया गया था।
- ईसाई मिशनरियों को अंग्रेजी का प्रचार करने और अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी।
- It brought an end to the monopoly of East India Company, over trade with India.
- Trade with India was opened for all British Citizens with the exception of Tea Trade.
- Permitted Christian missionaries to propagate English and preach their religion.

Charter Act of 1833

- बंगाल का गवर्नर-जनरल भारत का गवर्नर-जनरल बन गया।
- लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे।
- 1833 का चार्टर अधिनियम भारत में केंद्रीकरण की प्रक्रिया का अंतिम चरण था, एक प्रक्रिया जो 1773 के विनियमन अधिनियम के साथ शुरू हुई थी।
- एक भारतीय विधि आयोग की स्थापना की गई और लॉर्ड मैकाले इसके अध्यक्ष बने।
- Governor-General of Bengal became the Governor-General of India.
- Lord William Bentick was the 1st Governor-General of India.
- Charter Act of 1833 was the final step in the Process of Centralization in India, a process that began with the Regulating Act of 1773.
- An Indian Law Commission was established and Lord Macaulay as its chairman.

Charter Act of 1853

- सिविल सेवा परीक्षा शुरू की गई। यह सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा थी।
- गवर्नर-जनरल के कार्यकारी और विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया।
- 1853 के चार्टर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गवर्नर जनरल की विधान परिषद को केंद्रीय विधान परिषद के रूप में जाना जाने लगा।
- Civil Service Examination was introduced. It was a competitive examination for recruitment into the civil services.
- Executive and Legislative functions of the Governor-General were separated.
- As per provisions of Charter Act of 1853 Governor General's Legislative Council came to be known as the Central Legislative Council.

1857 → Revolt

ब्रिटिश ताज का शासन

Crown Rule

(1858-1947)

Government of India Act of 1858

- ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1858 के भारत सरकार अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। शक्तियां ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई।
- भारत के राज्य सचिव को पूर्व निदेशक मंडल के अधिकार और कर्तव्य दिए गए थे। उन्होंने भारत के वायसराय के माध्यम से भारतीय प्रशासन को नियंत्रित किया।
- Government of India Act of 1858 passed by British Parliament, brought an end to the rule of East India Company. The powers were transferred to the British Crown.
- The Secretary of State for India was given the powers and duties of the former Court of Directors. He Controlled the Indian Administration through the Viceroy of India.

Government of India Act of 1858

- भारत के राज्य सचिव को भारत की परिषद द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। इस परिषद में 15 सदस्य थे। परिषद एक सलाहकार निकाय थी।
- भारत के गवर्नर-जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया।
- लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे।
- The Secretary of State for India was assisted by the Council of India. This Council had 15 members. The Council was an advisory body.
- Governor-General of India was made the Viceroy of India.
- Lord Canning was the 1st Viceroy of India.

Indian Council Act of 1861

- भारतीयों को वायसराय की विधान परिषद में पहली बार गैर-सरकारी सदस्यों के रूप में मनोनीत किया गया था।
- इसने भारत की कार्यकारी परिषद को 'पोर्टफोलियो सिस्टम' पर चलने वाली कैबिनेट के रूप में कार्य करने के लिए बदल दिया।
- बंबई और मद्रास प्रेसीडेंसी को विधायी शक्तियां बहाल करके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की।
- Indians were nominated as non-official members for the 1st time in the Legislative Council of Viceroy.
- It transformed India's executive council to function as a cabinet run on the 'Portfolio system'.
- Initiated the process of decentralization by restoring the legislative powers to the Bombay and Madras Presidencies.

Indian Council Act of 1892

- विधान परिषद का आकार बढ़ाया गया।
- विधान परिषद को अधिक शक्ति दी गई थी, उनके पास बजट पर विचार-विमर्श करने की शक्ति थी और वे कार्यपालिका से प्रश्न पूछ सकते थे।
- पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव शुरू किए गए थे।
- The size of the Legislative Council was increased.
- The Legislative Council was given more power, they had the power to deliberate on the Budget and could pose questions to the Executive.
- Indirect elections were introduced for the 1st time.

Indian Councils Act, 1909 - Morley Minto Reforms

- पहली बार, विधान परिषदों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई।
- पृथक निर्वाचक मंडल देकर मुसलमानों के लिए साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत की गई।
- पहली बार भारतीयों को वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया गया था। सत्येंद्र सिन्हा विधि सदस्य थे।
- For the 1st time, Direct elections were introduced for the Legislative Councils.
- The Communal representation system for Muslims was introduced by giving separate electorate.
- For the first time, Indians were appointed to the Executive Council of Viceroy. Satyendra Sinha was the law member.

Government of India Act, 1919 – Montagu Chelmsford Reforms

- इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अब दो सदन शामिल थे- सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट।(द्विसदनात्मक व्यवस्था)
- प्रांतों को दोहरी सरकार प्रणाली या द्वैध शासन का पालन करना था।
- सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियन और यूरोपीय लोगों के लिए सांप्रदायिक मताधिकार का विस्तार।
- The Imperial Legislative Council was now to consist of two houses- the Central Legislative Assembly and the Council of State. (Bicameralism)
- The provinces were to follow the Dual Government System or Dyarchy.
- An extension of Communal franchise for Sikhs, Indian Christians, Anglo-Indian and European.

Government of India Act, 1919 – Montagu Chelmsford Reforms

- सिविल सेवकों की भर्ती के लिए 1926 में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी।
- वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों की संख्या आठ सदस्यों में से तीन होगी।
- A central public service Commission was set up in 1926 for recruiting civil servants.
- The number of Indians in Viceroy's Executive Council would be three out of eight members.

Government of India Act, 1919 – Montagu Chelmsford Reforms

- मताधिकार एक सीमित आबादी को दिया गया था जो उन लोगों पर आधारित थी जिनकी कर योग्य आय थी, संपत्ति थी और 3000 रुपये का भू-राजस्व दिया था।
- मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने सरकार के कामकाज को देखने के लिए 10 साल के अंत में एक वैधानिक आयोग की स्थापना का प्रावधान किया।
- The franchise was given to a limited population which was based on people who had taxable income, had property and paid land revenue of Rs 3000.
- Montagu Chelmsford Reforms made provision for setting up a statutory commission at the end of 10 years to look into the working of the Government.

Government of India Act 1935

- यह कई गोलमेज सम्मेलनों और साइमन कमीशन की एक रिपोर्ट का परिणाम था।
- प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में मिलाकर अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान था।
- अधिनियम के अनुसार, शक्तियों को संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया था।
- It was the result of multiple round table conferences and a report by the Simon Commission.
- There was provision for the establishment of All India Federation consisting of Provinces and the Princely States as units.
- As per the Act, the powers were divided into Federal List, Provincial List and Concurrent List.

Government of India Act 1935

- द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई।
- केंद्र में द्वैध शासन को अपनाने का प्रावधान था।
- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की स्थापना के लिए प्रावधान प्रदान किए।
- एक संघीय न्यायालय की स्थापना।
- बर्मा भारत से पूरी तरह अलग हो गया था।
- Provincial autonomy was introduced in the Provinces by abolishing the Dyarchy.
- There was provision for the adoption of Dyarchy at the Centre.
- Provided provisions for establishing Reserve Bank of India (RBI).
- The establishment of a Federal Court.
- Burma was completely separated from India.

Mountbatten Plan - Indian Independence Act - 1947

- 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश भारत का भारत और पाकिस्तान में विभाजन हुआ।
- संविधान सभा को पूर्ण विधायी अधिकार प्रदान किया।
- प्रांतों और राज्यों दोनों में सरकारों की स्थापना की।
- British India was partitioned into India and Pakistan with effect from 15th August 1947.
- Conferred complete legislative authority to the Constituent Assembly.
- Established Governments in both Provinces and States.

Key Timelines – Constitution of Independent India

- भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य पूरा करने के लिए संविधान सभा को लगभग 3 साल लग गए।
- 9 दिसंबर, 1946 को पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई।
- 14 अगस्त 1947 को; समितियों के गठन का प्रस्ताव था।
- The Constitution of India was drawn up by the Constituent Assembly. Constituent Assembly took almost 3 years to complete the task of drafting the Constitution for Independent India.
- Constituent Assembly met for the first time on Dec. 9, 1946.
- On 14th August 1947; there was a proposal for the creation of committees.

Key Timelines – Constitution of Independent India

- प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुई थी और संविधान सभा संविधान लिखने की प्रक्रिया शुरू करती है
- राष्ट्रपति के रूप में डॉ राजेंद्र प्रसाद ने फरवरी 1948 में स्वतंत्र भारत के नए संविधान का मसौदा तैयार किया।
- 26 नवंबर, 1949 को संविधान को अपनाया गया था।
- The Drafting Committee was established on 29th August 1947 and the Constituent Assembly starts the process of writing the Constitution.
- Dr Rajendra Prasad as the President prepared the Draft of the new constitution of Independent India in February 1948.
- The Constitution was adopted on Nov. 26, 1949

Key Timelines – Constitution of Independent India

- 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू हुआ, जिससे भारत एक गणतंत्र बना।
- उस दिन, विधानसभा का अस्तित्व समाप्त हो गया, 1952 में एक नई संसद के गठन तक खुद को भारत की अस्थायी संसद में बदल दिया।
- The Constitution came into effect on Jan. 26,1950, making India a Republic.
- On that day, the Assembly ceased to exist, transforming itself into the Provisional Parliament of India until a new Parliament was constituted in 1952.

भारतीय संविधान
Indian Constitution

- मूल रूप से, 26 नवंबर, 1949 को अपनाए गए संविधान में एक प्रस्तावना, 22 भागों में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में, 1950 में इसके अधिनियमन के बाद से 104 संशोधनों के कारण अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर 448 हो गई है। साथ ही, संविधान में अब 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं।
- Originally, the constitution adopted on November 26, 1949, contained a Preamble, 395 articles in 22 parts and eight schedules. Currently, the number of articles has since increased to 448 due to 104 amendments since its enactment in 1950. Also, the constitution now has 25 parts and 12 schedules.

Q.1 निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था?

Which of the following act was based on Montagu-Chelmsford Report?

a) Government of India Act, 1892

b) Government of India Act, 1909

c) Government of India Act, 1919

d) Government of India Act, 1935

Q.2 निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा धर्म के आधार पर एक अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत की गई थी?

A separate electorate on the basis of religion was introduced by which of the following acts?

a) Indian council act, 1909

b) Indian council act, 1892

c) Communal Award, 1932

d) Government of India Act, 1919

Q.3 किस अधिनियम के तहत इलाहाबाद में आईसीएस की पहली परीक्षा आयोजित की गई थी?

Under which Act was the first examination for ICS held in Allahabad?

a) The Morley-Minto Reform Act 1909

b) The Indian Councils Act of 1892

c) The Rowlatt Act of 1919

d) The Government of India Act 1919

Q.4 लॉर्ड कर्जन ने निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं अपनाया था?

Which one of the following measures were NOT adopted by Lord Curzon?

a) The Calcutta Municipal Amendment Act

b) Indian Universities Act

c) Indian Officials Secrets Amendment Act

d) Law for Protecting Ancient Indian Monuments

Q.5 1930 में निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग का अध्यक्ष था?

Who among the following was the President of the Muslim League in 1930?

H/W

a) Muhammad Ali Jinnah

b) Jawahar Lal Nehru

c) Sir Mohammad Iqbal

d) Maulana Azad